अरविन्द पाण्डेय

विद्यालयी शिक्षा मंत्री
उत्तराखण्ड सरकार

दिनांक 15 अगस्त, 2018

संदेश

विद्यालयी शिक्षा परिवार के समस्त छात्र–छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों, शैक्षिक अभिकर्मियों, शिक्षाधिकारियों एवं प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों को 72 वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, स्वतन्त्रता का आशय मात्र राजनैतिक रूप से सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य की स्थापना ही नहीं है अपितु नागरिकों को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वावलम्बन हेतु पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलम्बी बनाना है एवं भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करना है। इस दिशा में प्रदेश सरकार सतत् प्रयत्नशील है तथा राज्य के चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर है।

शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक, अभिकर्मी, प्रधानाचार्य एवं अधिकारियों का दायित्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे मूल्यवान धरोहर (अपना बच्चा) के सर्वांगीण विकास की अभिलाषा के साथ हमारे हाथों में सौंपता है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है यथा–उनके शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, मानसिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करते हुए उन्हें सुयोग्य नागरिक बनाना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संस्थाध्यक्ष अपनी योग्यता, ज्ञान, नेतृत्व शक्ति, अनुभव एवं विवेक के साथ कार्य करें।

स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर मेरा अनुरोध है कि बच्चों को भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन, देशभक्तों की गाथाओं तथा देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले शहीदों की शहादत से परिचित करवाया जाय।

छात्र–छात्राओं में नैतिक मूल्यों एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने तथा स्वतन्त्रता का आशय स्वयं ढूंढने की प्रवृत्ति विकसित किये जाने हेतु विद्यालयों में विभिन्न क्रिया कलापों का आयोजन किया जाय। साथ ही मानवाधिकार, न्यायिक संरचना, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता, स्वच्छता अभियान, आपदा प्रबन्धन, योग एवं स्वास्थ्य, हमारी लोक कलाओं/संस्थाओं आदि की सामान्य जानकारी देते हुए उनमें विद्यार्थी जीवन से ही आदर्श नागरिक के गुण विकसित करने पर ध्यान दिया जाय। हमारी सरकार छात्र–छात्राओं के समुचित पठन–पाठन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षकों के विरूद्ध विशेष अन्वेषण दल (एस0आई0टी0) से जाँच करायी गयी है तथा आरोपियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की गयी है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाने हेतु विभागीय अधिकारियों को सतर्कता अधिकारी का दायित्व भी सौंपा गया है, जो कि सरकार की सुराज–भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं पारदर्शी नीति को परिलक्षित करती है।

विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शैक्षिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कक्षा शिक्षण में नवीन शिक्षण तकनीकि के दृष्टिगत स्मार्ट कक्षाओं का संचालन भी किया जा रहा है। अधिगम सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने के निमित्त विद्यालयों में मासिक मूल्यांकन के द्वारा मासिक लक्ष्यानुश्रवण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम प्रदेश के विद्यालयों में लागू किया गया है। साथ ही सभी विद्यालयों में बुक बैंक स्थापित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया जा चुका है जिसमें उत्तीर्ण छात्र–छात्राऐं अपनी समस्त पुस्तकें बुक बैंक को दान स्वरूप दे सकेंगे जिनका उपयोग विद्यालय के निर्धन छात्र–छात्राऐं निःशुल्क कर सकेंगे। सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के

एकीकरण के फलस्वरूप कक्षा 1 से 12 तक समग्र शिक्षा अभियान का संचालन प्रारम्भ हो चुका है जिसके अन्तर्गत राज्य के 1218 विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक आई0सी0टी0 प्रयोगशालाएं स्थापित किये जाने, 475 आदर्श विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन एवं 200 विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक 09 ट्रेड के साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व Corporate Social Responsibility (CSR) के अन्तर्गत कई विद्यालयों को मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करायी गयी हैं। प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों की सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को प्रतिभा दिवस आयोजित किया जा रहा है। बाल सखा पोर्टल के अन्तर्गत जिज्ञासा लिंक द्वारा विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी/परामर्श दिया जा रहा है। न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों का विलीनीकरण करते हुए केन्द्रीयकृत विद्यालयों को साधन सम्पन्न बनाया जा रहा है। केन्द्रीयकृत विद्यालयों तक छात्र–छात्राओं की सुगम पहुंच बनाने के लिये एस्कोर्ट का प्रावधान किया जा रहा है। इसी के साथ समस्त कार्मिकों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमैट्रिक मशीनों का प्रतिस्थापन भी किया जा रहा है।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र–छात्राओं को पौष्टिक एवं ताजा भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधम सिंह नगर में अक्षय पात्र योजना के अन्तर्गत केन्द्रीकृत किचन के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 से सम्बद्ध निजी विद्यालयों द्वारा छात्रों से पुनः प्रवेश शुल्क, कॉशन मनी, कैपीटेशन शुल्क के नाम पर भारी धनराशि वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। सरकार ने इस दिशा में कठोर कदम उठाते हुए न केवल पुनः प्रवेश शुल्क, कॉशन मनी, कैपिटेशन शुल्क लेने पर रोक लगायी है, अपितु जो विद्यालय यह शुल्क ले चुके थे उनके अभिभावकों को शुल्क वापस भी कराया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक वर्ष शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है साथ ही परिषदीय परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रतिभावान छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों को भी प्रत्येक वर्ष गवर्नर्स एवार्ड से पुरस्कृत किया जा रहा है।

शिक्षकों एवं कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर कार्मिकों, शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों एवं विभागीय अधिकारियों को सीमैट, एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

इस अवसर पर मैं समस्त अभिभावकों से भी विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था के प्रति संवेदनशील रहने एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रति जागरूकता विकसित करने की अपेक्षा रखता हूँ।

अन्त में प्रदेश के शिक्षा परिवार से जुड़े समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं अधिकारियों को एक बार पुनः स्वतन्त्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

जय भारत, जय उत्तराखण्ड।

दिनांक
देहरादून

अरविन्द पाण्डेय
विद्यालयी शिक्षा, पंचायती राज,
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री,
उत्तराखण्ड सरकार